



दैनिक बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, में एक साथ प्रसारित ।

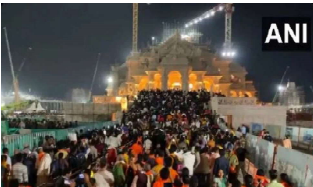
9415163471, 9453824459 Dainik Budh ka sandesh @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

संजय सिंह का बड़ा दावा: राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को सौंपेंगे

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनके पास अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के सबूत हैं और वे चंदे में हेराफेरी के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये दस्तावेज सौंपने की योजना बना रहे हैं। गुरवार को बोलते हुए सिंह ने कहा कि मेरे पास जमीन घोटाले से जुड़े कई सबूत हैं और मैं वे सभी दस्तावेज एसआईटी के सामने पेश करूंगा। अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। एसआईटी को लिखे एक पत्र में, सिंह ने कहा कि कथित गबन से लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने लिखा कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट द्वारा किए गए घोटालों से देश भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। हाल ही में, दान पेटी से करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नु यादव और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं।

पीएमओ के दखल के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट का इनकार, नहीं देंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड

अयोध्या । श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री और कुल संपत्ति का ब्योरा भी कार्यालय से मिली शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगी गई विस्तृत वित्तीय जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने 9 जून को PMO के पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की थी। शिकायत में राम मंदिर ट्रस्ट के बनने के बाद से आय और खर्च में पारदर्शिता की मांग की गई थी। साथ ही, मिले दान, बैंक अकाउंट के



पासपोर्ट बनवाना हो गया महंगा... नॉर्मल कैंटेगरी 2,500 और तत्काल में 5,000

सरकार ने गुरवार को लगभग 14 साल में पहली बार पासपोर्ट फीस बढ़ाई है। 1 जुलाई से नए पासपोर्ट की कीमत नॉर्मल स्कीम के तहत 2,500 रुपये और तत्काल स्कीम के तहत 5,000 रुपये हो जाएगी। यह नई फीस लिस्ट विदेश मंत्रालय (डफ़्) के उस स्पष्टीकरण के एक दिन बाद जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का सबूत। नई दरों के तहत, 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नया 36-पेज का पासपोर्ट या उसे दोबारा जारी करवाने का खर्च नॉर्मल स्कीम में 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगा, जबकि तत्काल फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, बंगाल, असम, गुजरात ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान और तेज किया

ढाका से लेकर गुवाहाटी और गुजरात तक फैले बांग्लादेशी घुसपैठ के जाल ने एक बार फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमा पर लगातार सख्ती के बावजूद घुसपैठियों के गिरोह नए रास्ते, नए दलाल और नए फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हालात इतने चिंताजनक हो चुके हैं कि अब यह केवल अवैध प्रवेश का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। ताजा घटना की बात करें तो आपको बता दें कि बांग्लादेश ने फिर आरोप लगाया है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने नौ लोगों को बांग्लादेश में भेजने की कोशिश की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने दावा किया कि नौगांव के सपाहार सीमा क्षेत्र में तीन पुरुष, तीन महिलाएं और तीन बच्चों को जीरो लाइन के पास रोका गया। बांग्लादेशी बलों का कहना है कि उनकी कड़ी चौकसी के कारण इन लोगों को देश में घुसने नहीं दिया गया और वे सीमा पर ही फंसे रहे। इस पूरे मामले पर भारतीय पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन यह घटना सीमा पर लगातार बढ़ रही हलचल को साफ दिखाती है।

इमरजेंसी के 50 साल: रविशंकर प्रसाद बोले

इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने को लगाई थी इमरजेंसी

नई दिल्ली। गुरवार को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का मकसद सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाना था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि यह मौका इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं की याद दिलाता है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप



लगाया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज लोग देश में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और संविधान दिखाते हैं। आज, इन 50 सालों में, उनके असली चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है कि 50 साल पहले क्या हुआ

था। मैं श्रृंखला आंदोलन का एक सिपाही था। मुझे इमरजेंसी के दौरान लड़ने का सीमाग्य भी मिला। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट गई थी। इससे पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 जून, 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया और कहा कि इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचाया। केंद्र सरकार द्वारा श्रृंखला हत्या दिवस के तौर पर मनाए जा रहे इमरजेंसी के 51वें साल के मौके पर, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उस दौर में नागरिक अधिकारों को दबाया गया, प्रेस की आजादी पर रोक लगाई गई और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई गईं।

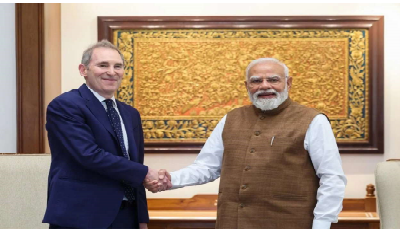
लेकिन उन्हें रोक (जंजल) नहीं मिलीय कहा गया कि आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगी। इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल किया गया। इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लगाई गई

एसआईटी ने गड़बड़ियों की ओर इशारा किया

राम मंदिर में दान के पैसे के कथित गलत इस्तेमाल की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट में दान की गिनती और उसकी निगरानी के तरीके में गंभीर खामियों की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में दान संभालने की व्यवस्था में खराब निगरानी और जवाबदेही में कमियों को लेकर चिंता जताई गई है। जांच के इस चरण में, एसआईटी ने इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच टीम ने इस बात की भी जांच की है कि दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों का चयन कैसे किया गया। टीम ने इन लोगों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की है।

अमेजन का भारत में रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर का निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले— युवाओं के लिए खुलेंगे नए मौके

नई दिल्ली। अमेजन के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह बयान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेजन के सीईओ एंडी जैसी के बीच हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद आया, जिसमें इस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने घोषणा की कि वह 2026 और 2030 के बीच भारत में 48 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मिस्टर एंडी जैसी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैं भारत में अमेजन के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करता हूँ। इससे हमारे युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे। साथ ही, इससे पता चलता है कि



दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का यह पोस्ट अमेजन के सीईओ एंडी जैसी के उस पोस्ट के जवाब में था, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया था कि अमेजन अगले पांच सालों में भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

एंडी जैसी ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में अमेजन के भविष्य को लेकर हुई मीटिंग बहुत अच्छी रही। हम एक दशक से ज्यादा समय से भारत में कस्टमर्स, सेलर्स, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेज को सर्विस दे रहे हैं और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। मैंने बताया कि हम अगले पांच सालों में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जिसमें एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 21 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश शामिल है। 2030 तक, हमारी योजना 38 लाख (3.8 मिलियन) नौकरियों को सपोर्ट करने, 80 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और 1.5 करोड़ (15 मिलियन) छोटे व्यवसायों और 40 लाख (4 मिलियन) सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स तक एआई के फायदे पहुंचाने की है।

भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। हम जो कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। जैसी ने आगे कहा हमने 2010 से भारत में 40 अरब USD का निवेश किया है। और फिर पिछले साल के आखिर में हमने घोषणा की थी कि हम 2026 और 2030 के बीच भारत में 35 अरब USD का निवेश करेंगे। और आज हमने घोषणा की है कि हम उस रकम को 35 अरब से बढ़ाकर 2026 और 2030 के बीच कुल 48 अरब USD का निवेश करेंगे। इस बड़े हुए फाइनेंशियल कमिटमेंट की मुख्य वजह डिजिटल इकॉनमी में बढ़ती मांग है, जिसके कारण कंपनी ने दशक के आखिर के समय के लिए तय शुरुआती 35 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाकर और ज्यादा रिसोर्स लगाने का फैसला किया है।

आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय: मुख्यमंत्री योगी

लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये की नकदरहित स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की भी बनेगी व्यवस्था

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा, नागरिक अधिकारों को कुचला और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई बताना आवश्यक है, ताकि



लोकतंत्र के महत्व और उसकी रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को भुलाया न जा सके। मुख्यमंत्री गुरवार को लखनऊ में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस'

एवं 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और उनके योगदान को लोकतंत्र की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों और लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाने का काम किया।

यूपी बीजेपी ने कसी चुनावी कमर

नई टीम में राजनाथ सिंह के बेटे और कई युवा चेहरे शामिल

लखनऊ। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में एक अहम बदलाव करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने पंकज चौधरी के नेतृत्व में अपनी नई राज्य संगठन टीम की घोषणा की है। यह फैसला दिल्ली और लखनऊ में हुई कई अहम बैठकों के बाद लिया गया, जिनमें राज्य में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इन नामों को उश्र्च के शीर्ष नेतृत्व ने मंजूरी दी। नई घोषित राज्य संगठन टीम, अहम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर नेटवर्क को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को बेहतर बनाने की पार्टी की रणनीति को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश उश्र्च की ओर से जारी



19 उपाध्यक्ष और आठ महासचिव शामिल हैं। प्रमुख नियुक्तियों में, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को राज्य का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री सुरेश राणा, अर्चना मिश्रा और पूजा पाल को भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब BJP 2029 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उत्तर प्रदेश के अहम

विधानसभा चुनावों की तैयारी में है। संजय राय को राज्य महासचिव नियुक्त किया है, जबकि बीजेपी के राजेश चौधरी को भी जम्मेदारी दी गई है। जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अलग-अलग इलाकों और सामाजिक समूहों में संगठन को मजबूत करने की बड़ी कोशिश के तहत, बीजेपी ने अभिजात मिश्रा, शंकर लोधी और दिलीप पटेल को भी राज्य महासचिव नियुक्त किया है। इसी के साथ, पार्टी

वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान इन बातों ...8

बलरामपुर

शुक्रवार , 26 जून 2026

वर्ष: 05 अंक : 265 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

एक विश्वास...

सम्पादक : राजेश शर्मा

साम्पादकीय

मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति–निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे। साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है...

मुकाबले को युद्ध स्तर पर हो तैयारी

दक्षिण–पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बलवती हुई है। हाल–फिलहाल बारिश में चालीस से छियालीस प्रतिशत की कमी मापी गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के अनुमान के कारण खरीफ की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं। जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देशी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने–पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है। साथ ही कोशिश है कि किसानों के लिये बीज–उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती हैं। सुखद ही है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये रियल–टाइम सलाह किसानों को देकर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है। आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिये एक प्रभावी समय नीति बने। समय–समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाए। जरूरी है कि

जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिये जरूरी है कि सूक्ष्म–सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल निकायों के पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। हम मौसम के बदलते मिजाज पर हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। हमें किसानों को आर्थिक संकट से उबारने को अपनी वरीयता सूची में शामिल करना चाहिए। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा के लिये बीमा कवरेज अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। किसानों को फसलों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा लेने के बारे में व्यावहारिक जानकारी अक्सर कम ही होती है। वैसे तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण है और आपातकालीन व्यवस्था के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमें लाखों किसानों का जीविका संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मौसम के मिजाज में होने वाला बदलाव अब कभी–कभार की बाधा नहीं रही, बल्कि बार–बार होने वाली सच्चाई बन गया है। मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति–निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे। साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। देश में जलाशयों के जल का किफायती उपयोग हो। निस्संदेह, कम बारिश से केवल किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती है, सूखे में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने पर अनाज महंगा होने से आम आदमी का जीवन भी बाधित होता है। जिससे किसान की ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

पैसा और पॉवर मगर औकात सच बोलती है

पॉवर और पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाते, केवल उसके भ्रम का आकार बढ़ा देते हैं। हरियाणा में कहावत है भैंस के सींग दिख जाते हैं, सत्ता के सींग दिखाई नहीं देते... पर मार दोनों की बराबर पड़ती है। एक चौधरी के हाथ पहली बार सौ रुपये का नोट लगा तो सीधा गांव के बनिये की दुकान पर पहुंच गया। चौधरी ने पूछा कि उसके पास भी सौ रुपये का नोट है? बनिया घबरा गया। उसने झट से अपनी तिजोरी बंद की और सावधानी से बोला, हां चौधरी, मेरे पास तो सौ के कई नोट हैं। चौधरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछने लगा कि इतणे सारे नोटां के होते होये भी तू चुचाप बैझा सै? मेरे धोरे तो एकै नोट आया सै, अर जी कर धंया सै किसी का सिर फोड़ दूं। पैसा और पॉवर हैं ही ऐसी चीज। इतिहास गवाह है कि पॉवर पाना कठिन अवश्य है पर उससे कहीं अधिक कठिन है उसे पचाना। इसीलिये कहा जाता है कि लोकतंत्र में कुर्सियां बदलती रहनी चाहिए क्योंकि कुर्सी पर जमी धूल से ज्यादा खतरनाक उस पर जमी हुई अकड़ होती है। पॉवर और पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाते, केवल उसके भ्रम का आकार बढ़ा देते हैं। हरियाणा में कहावत हैकू भैंस के सींग दिख जाते हैं, सत्ता के सींग दिखाई नहीं देते... पर मार दोनों की बराबर पड़ती है। पैसा आते ही कई लोगों का हाल उस बछड़े जैसा हो जाता है जो पहली बार सींग निकलते ही समझने लगता है कि सारे खेत का मालिक वो ही है। कुर्सी मिली ना, अर चाल ऐसी बदल ली जैसे दिल्ली का लाल किला भी बाप–दादा की जागीर हो। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो पर सत्ता आने पर आदमी अपनी चादर छोड़ कर पड़ोसी के बिस्तर में भी पैर पसारने लगता है। मुझे तो लगता है कि पॉवर चीज ही ऐसी है कि खूंटी पै टंगी लाटी भी खुद को चौधरी समझने लगती है। आजकल सौ रुपये के नोट की जगह पॉवर ने ले ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब नोट जेब में नहीं, पद जेब में रखा जाता है। किसी को वार्ड का प्रधान बना दो, उसकी चाल बदल जाती है। किसी को समिति का सदस्य बना दो, फोन उठाने का अंदाज बदल जाता है। किसी को बोर्ड का चेयरमैन बना दो, उसे लगता है संविधान उसी की जेब में रखा है। कोई मंत्री बन जाए तो उसे ट्रैफिक का लाल सिग्नल भी अपनी इज्जत के खिलाफ लगता है। कुर्सी चाहे चार पैरों पर खड़ी होती है पर उस पर बैठते ही कई लोगों के दोनों पैर जमीन से उठ जाते हैं।

राष्ट्रपति भवन में भी कहानी सुनाते वक्त ऐसा अनुभव हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती, जिसमें बच्चों के लिए कोई संदेश न छिपा हो। लेकिन उन्हें सीधे–सीधे संदेश देने से बचा जाता है। ये कहानियों की बुनावट के अंदर ही होने चाहिए। इन दो दिनों में पहले दिन जब एक यथार्थवादी कहानी, जिसमें एक घायल बिल्ली के बच्चे की मदद और पर्यावरण तथा पानी की कमी की बात की ...

जिस अल्फा जेनरेशन के ये बच्चे हैं, वे यथार्थवादी कहानियों के मुकाबले, वे कहानियां सुनना, सुनाना चाहते हैं, जिनमें उन्हें अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाने का भरपूर मौका मिले। जहां उनकी कल्पना की राह में कोई रोड़ा न अटका हो, जिनमें भरपूर एक्शन, एडवेंचर हो। ऐसी बातें हों, जो कभी देखी, सुनी न हों। पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में दो दिन बच्चों को कहानी सुनाने और उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला। अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाना होता है जहां बहुत से बच्चे होते हैं, जिनमें दो–तीन साल के शिशु से लेकर चौदह–पंद्रह साल के बच्चे शामिल हैं। उनसे खूब बातें होती हैं। उनके साथ खेलना होता है। वे क्या पढ़ते हैं, इस बारे में भी अवश्य पूछती हूं। ये वे बच्चे हैं, जिनके माता–पिता युवा हैं। इनमें से भी बहुतों को कहानियां सुनाई हैं। आज उनके बच्चे सामने हैं, जिन्हें अल्फा जेनरेशन कहा जाता है। इस पीढ़ी के बारे में मशहूर है कि यह तो मोबाइल फोन ही हाथ में लेकर जन्मी है। यानी कि कोई भी सूचना इनके लिए नई नहीं है। जब हैरी पॉटर ने धूम मचाई थी, उस समय एक

बड़ा लेख लिखा था कि इसकी सफलता का कारण हार्श मार्केंटिंग, वर्ल्ड वाइड लांच और बुक स्टोर्स को पांच हजार पार्टियां देने के अलावा, यह भी था कि पश्चिम के बच्चे, तमाम तरह के गिजमोज और तकनीक से ऊब चुके थे। उन्हें जीवन में ऐसा कुछ चाहिए था, जिससे वे रोमांचित हो सकें। एक जमाने में अपने यहां बाल साहित्य को लेकर दो धाराओं में काफी बहस होती रही है। एक धारा कहती थी कि बच्चों को राजा–रानी, परी कथाएं, जिनके पात्र सिर्फ परियां ही नहीं, राक्षस, बौने, जादूगर, कोई चलने वाला पेड़, कोई बोलने वाला बाघ आदि होते थे, सुनाई जानी चाहिए। दूसरी धारा कहती थी कि बच्चों को वे कहानियां नहीं सुनाई, पढ़ानी चाहिए, जिनमें चमत्कार हों। वे चमत्कार की तरफ झुकें। तरह–तरह के अंधविश्वास उनके मन में न घर करें। इसलिए उन्हें वे कहानियां दें, जो उनके दैनंदिन जीवन से जुड़ी हों। यानी कि यथार्थवादी हों।



क्योंकि बच्चे किसी चमत्कार के जरिए जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। परिश्रम से ही उन्हें सफलता मिलती है। ये बात सच भी है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं और कोई चमत्कार बच्चे को सफलता दिला सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे इन बातों को जानते नहीं हैं कि अगर पढ़ेंगे नहीं, तो सफल होना मुश्किल है। अपनी नौकरी के दौरान पाया कि जब भी यथार्थवादी कहानियों पर अंक निकाले, उन्हें वह सफलता नहीं मिली जितनी कि राजा, राजी, वेद, पुराण, उपनिषद, कथा सरित्सागर, राजतरंगिणी

अल्फा जेनरेशन को भाती है अपनी कल्पना की उड़ान

महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश या ईसप की कथाओं को मिली। कई बार तो ऐसा हुआ कि ये अंक इतने बिके कि दोबारा छापने पड़े। इसके अलावा दैनंदिन जीवन की कथाएं कि बच्चों के बस्ते का बोझ कितना ज्यादा है, उन्हें पढ़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें अपने मित्रों से किस तरह के धोखे मिलते हैं, या कि किसी गरीब बच्चे के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, इन्हें आम तौर पर बच्चे सुनना नहीं चाहते। इससे ये निष्कर्ष भी निकला कि बच्चे जिन आफतों को रोजमर्रा के जीवन में भुगत रहे हैं, अगर आप उनका मनोरंजन करने आए हैं और उन्हें कहानियां भी यही सुना रहे हैं, तो वे हूट कर देते हैं। फिर जिस वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, तार्किकता को बढ़ाने आदि की बातें की जाती हैं, उनमें एक दिक्कत यह भी है कि विज्ञान प्रति पल बदलता है। आज एक खोज कुछ कहती है, तो दूसरी खोज बिल्कुल उसके विपरीत बातें करती है, तो आखिर किस बात को सच माना जाए। यों भी विज्ञान को किसी रुढ़ तर्क और अर्थ में बांधा भी नहीं जाना चाहिए। फिर जिन्हें परीकथा कहा जाता है, वहां भी तर्क नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसे फंटेसी कहा जाता है, वहां भी किसी कहानी में अच्छाई पर बुराई की विजय नहीं दिखाई जाती। न ही यह बताया जाता है कि सच के मुकाबले झूठ बोलना कितनी अच्छी बात है या कि पर्यावरण को नष्ट करना ठीक है। अथवा किसी जीव को सत्ता, किसी गरीब की मदद न करना, अपने बड़ों

की बात न मानना ही बढ़िया है। फंटेसी के भी बहुत मानवीयता वाले तर्क होते हैं। अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान बहुत से भारतीय और विदेशी बच्चों से मिली हूं। वहां भारतीय बच्चे अपने देश के मिथकीय चरित्रों जैसे कि श्रीराम, रावण, श्रीकृष्ण, दुर्योधन, बाल गणेश, काली, बाल हनुमान, मय दानव, अंगद, बाली, शिव, पार्वती, महाभारत की कथाएं, जटायु, पंचतंत्र की जानवरों की कथाएं आदि को बहुत चाव से पढ़ते मिले। जैसे ही किसी वैज्ञानिक चीज के बारे में उनसे बात की गई, वे फौरन अपना मोबाइल दिखाकर कहने लगे कि ये बात उन्हें पहले से मालूम है। जैसे कि चांद के बारे में कहा जाता है कि वहां न आक्सीजन है, न पानी, न पेड़, पौधे, न कोई इन्सान। इसलिए इन दिनों बच्चों को चांद के बारे में यदि कोई चमत्कारिक कथा सुनाई जाए, तो वे नहीं सुनेंगे। लेकिन एक कहानी सेशन के दौरान बच्चों ने चांद के बारे मे ऐसी–ऐसी परिकल्पनाएं कीं कि लगा कि वे अब भी चांद को लेकर बहुत–सी कहानियां सुन सकते हैं, बुन सकते हैं। यथार्थ चांद कैसा है, इससे

उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस अल्फा जेनरेशन के ये बच्चे हैं, वे यथार्थवादी कहानियों के मुकाबले, वे कहानियां सुनना, सुनाना चाहते हैं, जिनमें उन्हें अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाने का भरपूर मौका मिले। जहां उनकी कल्पना की राह में कोई रोड़ा न अटका हो, जिनमें भरपूर एक्शन, एडवेंचर हो। ऐसी बातें हों, जो कभी देखी, सुनी न हों। इनके आसपास न हों। कुल मिलाकर फंटेसी की वह दुनिया, जिसमें वे नायक की भूमिका या किसी योद्धा की भूमिका में हों। इस तरह की कहानियों में बच्चों के मस्तिष्क में कब, क्यों, कहां, किसलिए, अच्छा, ऐसा, वैसा, क्या ऐसा हो सकता है, आदि के तर्क चलते हैं।

सिद्धार्थगंगार का सबसे बड़ा फ़िटींग पब्लिकेशन हाउस... किसी भी कच्चे अंकित अक्षर को आकार दे

बुद्ध पब्लिकेशन

ऑफ़सेट एण्ड प्रिन्टर्स

www.budhakasandesh.com

8795951917, 9453824459

खेसरहा में मनरेगा में फर्जी हाजिरी का बड़ा खुलासा, महिला मेट बरवास्त, प्रधान समेत तीन से जवाब–तलब

दैनिक बुद्ध का संदेश / शशांक मिश्रा

खो सरहा। जनपद शुरू कराई। रिकॉर्ड में 148 सिद्धार्थनगर के खेसरहा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बनकटा प्रथम में मनरेगा कार्यों में कथित फर्जी हाजिरी और अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शिकायत को गंभीर मानते हुए एक महिला मेट को पद से हटा दिया गया है, जबकि ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) और रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पीजी पोर्टल पर शिकायत से खुला मामला: जानकारी के अनुसार, आजाद अधिकार सेना के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पूर्वांचल जितेंद्र कुमार पाण्डेय ने पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत की प्रतियां ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आयुक्त, जिलाधिकारी तथा डीसी शिकायत में यह भी कहा गया मनरेगा को भी भेजी गई थीं। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच



कि ग्राम पंचायत बनकटा प्रथम में संचालित एक मनरेगा कार्यस्थल पर जारी मास्टर रोल संख्या 1143 से 1157 तक दर्ज श्रमिकों की संख्या और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था। शिकायतकर्ता का दावा है कि 1 जून से 4 जून 2026 के बीच कार्यस्थल पर सीमित संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे, जबकि एनएमएमएस (छड्डे) ऐप पर 148 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर उनकी तस्वीरें अपलोड की गईं। शिकायत में यह भी कहा गया कि बाद के दिनों में भी कार्यस्थल पर पर्याप्त मजदूर मौजूद नहीं थे, फिर भी उपस्थिति दर्ज होती

रही। इससे मनरेगा में पारदर्शिता और सरकारी धन के उपयोग पर सवाल खड़े हो

गए। फोटो और मोबाइल डिवाइस की जांच की मांग: शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की कि एनएमएमएस ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों का वास्तविक स्थिति से मिलान कराया जाए। साथ ही फोटो अपलोड करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन अथवा अन्य डिवाइस की तकनीकी जांच भी कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उपस्थिति किस प्रकार दर्ज की गई और कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। प्रशासन ने दिखाई सख्ती: मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी ने

जांच कराई। प्रारंभिक जांच में अनियमितता के संकेत मिलने पर संबंधित महिला मेट को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम:स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्रामीणों की निगाहें अब आगे की जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कथित फर्जी हाजिरी के पीछे कौन–कौन जिम्मेदार हैं और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।

मोहरम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम व एसपी ने किया बडहरागंज गांव का निरीक्षण, दिया निर्देश

कुशीनगर। जनपद में आगामी मोहरम पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के मद्देनजर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संयुक्त रूप से पडरौना कोतवाली थाने के मिश्रौली पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बडहरागंज स्थित कर्बला एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं भ्रमण कर पर्व को शांति पूर्वक मनाने की अपील की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मोहरम से संबंधित व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों तथा जुलूस मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्व के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय नागरिकों, धर्मगुरुओं एवं सभ्रांत व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर उन्हें प्रशासन की ओर से पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जनपद प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन मोहरम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आमजन से आपसी भाईचारा, सौहार्द एवं शांति बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा समस्या की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को उपलब्ध कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। जनपद प्रशासन द्वारा मोहरम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

हादसे के बाद जागने की परंपरा ?कुशीनगर में नियम ताक पर, खतरे में छात्र और पर्यटक

कुशीनगर के होटल, कोचिंग सेन्टर, लाइब्रेरी और रेस्तेरेंटों में मौत का इंतजाम।

कुशीनगर। राजधानी लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुशीनगर में मानो इस घटना से कोई सीख नहीं ली गई है। जिले में संचालित होटल, रेस्तेरेंट, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। अधिकांश संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है, अग्निशमन यंत्र या तो नहीं हैं या सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाए गए हैं।

ऐसे में ये संस्थान किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। बुद्ध मंदिर मार्ग समेत जिले के विभिन्न कस्बों और नगर क्षेत्रों में दर्जनों होटल–रेस्तेरेंट संचालित हो रहे हैं। वही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और 24 घंटे चलने

वाली लाइब्रेरियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इनमें रोजाना सैकड़ों छात्र–छात्राएं और पर्यटक आते–जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। बताते चले कि जिले में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां तंग गलियों, बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रही हैं। अधिकांश स्थानों पर आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि आग या अन्य आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो छात्रों के सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं है। लखनऊ हादसे ने दिखा दिया कि थोड़ी सी लापरवाही किस तरह से ज़िंदगियों को निगल सकती है। इसके बावजूद कुशीनगर में

आईजीआरएस रिपोर्ट पर उठे सवाल : जांच में हटाई गई प्लाटिंग, लेकिन उसी जमीन पर जारी रजिस्ट्रियां

दैनिक बुद्ध का संदेश



शोहरतगढ़। भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे खुनुवा में अवैध प्लाटिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत संख्या 40018426001069 के संबंध में प्रशासन द्वारा दिए गए जवाब में दावा किया गया कि मौके की जांच कर अवैध प्लाटिंग को हटवा दिया गया है और अब वहां कोई अवैध गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन सामने आए एक विभागीय पत्र ने इस पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।प्राप्त पत्र के अनुसार, पिकायत की जांच के दौरान यह स्वीकार किया गया कि ग्राम खुनुवा, तहसील शोहरतगढ़ में संबंधित

गाटा संख्या 313 में प्लाटिंग के संबंध में जेसीबी के द्वारा मौके पर की गयी गई अवैध प्लाटिंग को हटवा दिया गया है। इतना ही नहीं, पत्र में यह भी उल्लेख है कि उक्त भूमि अन्तर्गत धारा – 80 एवं यूपीआरसी – 2006 आकृशक व जिला पंचायत से अनुमति व नक्सा पास कराये बिना प्लाटिंग और कॉलोनी का कार्य किया जाना नियम विरुद्ध पाया गया। इसके चलते संबंधित व्यक्ति को यह कहा गया धारा 80,जिला पंचायत से अनुमति एवम नक्सा पास कराने के उपरांत ही प्लाटिंग आदि कार्य किया जाय अन्यथा की दषा मे विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्रेषित कर दी जायेगी।

इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस प्लाटिंग को कागजों में हटाया हुआ दर्शाया गया और जिसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई, उसी भूमि पर आज भी धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां जारी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि अवैध प्लाटिंग समाप्त हो चुकी थी तो फिर रजिस्ट्रियां किस आधार पर हो रही हैं? और यदि कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है तो अब तक दोशियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई ‘? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी निशपक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप है कि भ्रामक रिपोर्टों के

बिजली विभाग मे भर्ती घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश? खुलासे के बाद भी जांच नहीं

कुशीनगर। बिजली विभाग में कथित रूप से लाखों रुपये लेकर की गई कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्तियों का मामला सामने आने और मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बावजूद अब तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं की गई है। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल और गहरे हो गए हैं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी भी संदेहों को बल दे रही है।

बीते दिनों मीडिया द्वारा प्रकाशित खबर में यह गंभीर आरोप सामने आया था कि आउटसोर्सिंग कम्पनी ने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, बिना मेरिट सूची और बिना पारदर्शी चयन प्रक्रिया के दर्जनों युवाओं को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक वसूले गए हैं। लेकिन खबर प्रकाशित होने के

कई दिन बाद भी न तो विभागीय जांच बैठी और न ही किसी अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया के सफाई में अपना मुंह खोलने की जहमत उठाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो विभाग अब तक चयन से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा? नियुक्त कर्मचारियों की सूची, आवेदन प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रति, चयन समिति का गठन और मेरिट का आधार आखिर जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में भी नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि यदि नियुक्तियां पहले से तय थीं तो जिले के हजारों शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन का अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकारी विभागों से जुड़ी नौकरियां अब आम युवाओं की पहुंच से बाहर होकर केवल पैसे वालों तक सीमित हो गई हैं? चर्चा

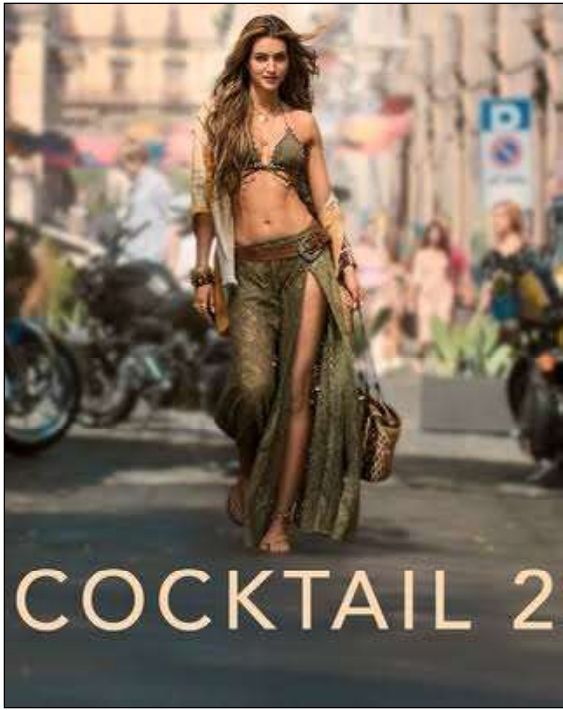
यह भी है कि भर्ती के इस कथित खेल में सिर्फ आउटसोर्सिंग कम्पनी ही नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण प्राप्त है। जिसके चलते नियुक्तियां होती रहीं और किसी स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा? मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि खुलासे के बाद भी प्रशासनिक खामोशी बरकरार है। आमतौर पर ऐसे गंभीर आरोप सामने आने पर प्रथम दृष्ट्या जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदार विभाग और जिला प्रशासन दोनों मौन दिखाई दे रहे हैं। यह मौन स्वयं कई सवाल खड़े कर रहा है। कहना न होगा कि जिले के बेरोजगार युवाओं और आम जनता की निगाहें जिला प्रशासन तथा विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं। सब यह है कि आरोप निराधार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप

से खारिज किया जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि मामला केवल 17 नियुक्तियों का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के विश्वास का है जो आज भी योग्यता के दम पर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। उठ रहे सवाल का जबाब नहीं दे रहा है विभाग— बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर आप्रैटरों की हुई भर्ती का विज्ञापन कब और कहाँ प्रकाशित हुआ?, आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने किया था?, चयन समिति में कौन–कौन शामिल थे?, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची कहां है? यह सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो विभाग दस्तावेज सार्वजनिक करने से क्यों बच रहा है? आखिर खबर छपने के बाद भी जांच शुरू क्यों नहीं हुई? इन सवालों का जवाब मिलने तक भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह खत्म नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य मिठाई लाल ने खड़ा तहसील में की जन सुनवाई

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य मिठाई लाल की अध्यक्षता में खड़ा तहसील सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं शत–प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण केवल औपचारिकता अथवा कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर मामलों की जांच करें तथा पीड़ितों को वास्तविक न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध ढंग से न्याय एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्व, पुलिस, विकास एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दिया कि यदि किसी भी स्तर पर शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने अथवा टालमटोल करने की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सदस्य ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर आने वाले फरियादियों को बार–बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए जवाबदेही तय करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपजिलाधिकारी खड़ा सर्वेश कुमार सिंह गौर, क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार सहित राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कॉकटेल 2 का दुनियाभर में गदर, रिलीज के 5 दिन में जड़ दिया शतक, ये रिकॉर्ड भी बनाया



मैडॉक फिल्मस की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस धाक जमाए हुए है. शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, फिल्म ने वीकडेज में भी अपनी रपतार बनाए रखी है. हालांकि इसकी कमाई में नॉन हॉलीडे पर मंदी भी देखी जा रही है लेकिन फिर भी ये हर दिन करोड़ों छाप रही है. रिलीज 5वें दिन तो शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने दुनियाभर में शतक जड़ दिया.

सिनेमाघरों में रिलीज होने के सिर्फ 5 दिनों में ही शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाल कर दिखाया है. दरअसल ये फिल्म 100 करोड़ के पार हो गई है. मानव मंगलानी द्वारा

शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 ने रिलीज के 5 दिनों में दुनियाभर में 106.61 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है. शानदार ओपनिंग वीकेंड और दमदार सोमवार के बाद, कॉकटेल 2 ने मंगलवार को भी जबरदस्त परफॉर्म किया और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 106.61 करोड़ तक पहुंच गई. दर्शकों का फिल्म के प्रति बढ़ता प्यार इसे ब्लॉकबस्टर बनाता है और इसकी रपतार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.

पोस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 24 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 29.4 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 32.19 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़ और 5वें दिन 11.01 करोड़ का कलेक्शन किया. शाहिद कपूर की फिल्म दुनिया भर में पांच दिनों में 106.61 करोड़ की कमाई करने के बाद साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 हिंदी फिल्मों की लिस्ट में ऑफिशियली शामिल हो गई है.

थलाइवर 173 का टाइटल रिवील, कमल हासन की फिल्म धर्मन: द डेडली डॉक्टर से रजनीकांत का फर्स्ट लुक आउट, डॉक्टर के कपड़े और पैरों तले लाश



तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर धमाल मचाने आ रही है. फिल्म मेकर ने थलाइवर 173 के टाइटल का एलान कर दिया है. थलाइवर 173 को धर्मनरू द डेडली डॉक्टर टाइटल दिया गया है. साथ ही फिल्म के हीरो रजनीकांत का भी फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. रजनीकांत फिल्म से आए अपने फर्स्ट लुक में बहुत ही स्वेग में दिख रहे हैं. फिलहाल यह खुलासा नहीं किया गया है कि फिल्म कब तक रिलीज होगी.

फिल्म धर्मन से आए फर्स्ट लुक में रजनीकांत का अलग ही स्वेग देखने के मिल रहा है. वह ब्लू कॉस्ट्यूम हैं और उनके हाथ खून से सने हैं. इनके पैरों के नीचे एक गुंडा जख्मी पड़ा है. रजनीकांत ने उसकी छाती पर मुस्कुराते हुए पैर रखा हुआ है. थलाइवा ने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं और वह एक ऑपरेशन थिएटर में दिख रहे हैं. बता दें, फिल्म का निर्देशन अश्वथ मरिमुथु कर रहे हैं और इससे पहले फिल्म का निर्देशन करने के लिए सुंदर का नाम आ रहा था. अश्वथ मरिमुथु साल 2025 में रिलीज हुई ड्रैगन और ओह माई कडावलु से पॉपुलर हैं. इससे पहले 5 नवंबर 2025 को कमल हासन और मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आधिकारिक एलान किया था कि सुपरस्टार रजनीकांत आगामी फिल्म थलाइवर 173 में अभिनय करेंगे. कमल हासन

और रजनीकांत की एक तस्वीर के साथ इसकी आधिकारिक एलान किया गया था. यह फिल्म 2027 में पोंगल के मौके पर रिलीज होने जा रही है होगी. अपने प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान को एक्स हैंडल पर साझा करते हुए कमल हासन ने एक तमिल कविता लिखी थी, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, हवा की तरह, बारिश की तरह, नदी की तरह, हम बहेंगे, चलो बारिश करें, आनंद लें, जीएँ. सुपरस्टार रजनीकांत सुंदर सी की निर्देशित और राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल की निर्मित फिल्म में अभिनय करेंगे. मेकर्स की ओर से एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था, सुपरस्टार रजनीकांत कमल हासन की राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल बैनर तले बनी फिल्म थलाइवर 173 में मुख्य भूमिका में नजर आए. उनके प्रोडक्शन हाउस के बयान में कहा गया था, सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन के राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल बैनर तले थलाइवर 173 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

बेहद हसीन दिखती हैं ईठा एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक में लगती हैं कमाल

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ईठा को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में श्रद्धा तमाशा कलाकार, लावणी डांसर और लोक गायिका विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका



निभा रही हैं. श्रद्धा अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में रहती हैं. फिल्म ईठा का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिसर्पोंस मिल रहा है. श्रद्धा कपूर ने एक बार फिर अपनी शानदार एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया है. फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ-साथ श्रद्धा कपूर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं. उनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं. श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल, श्रद्धा हर स्टाइल को बेहद ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं. श्रद्धा की सादगी और चार्म ही उन्हें बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेस से अलग बनाता है. उनका फैशन सेंस भी काफी यूनिक है. वो ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ-साथ अपना अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी बनाती हैं. श्रद्धा अपनी नेचुरल ब्यूटी को लेकर भी फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. उनकी खूबसूरत स्माइल और पॉजिटिव पर्सनेलिटी हर आउटफिट में झलकती है. चाहे श्रद्धा कपूर सिंपल कैजुअल लुक में हों या फिर किसी ग्लैमरस अवतार में, श्रद्धा अपनी सादगी और एलिगेंस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. श्रद्धा का मेकअप स्टाइल बेहद सॉफ्ट और नैचुरल रहता है, जो उनकी फीचर्स को और ज्यादा निखार देता है. वो अक्सर स्मोकी आईज, सॉफ्ट लिप्स और हल्के ग्लोइंग मेकअप के साथ नजर आती हैं. श्रद्धा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 93.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर नए लुक का फैंस बेसव्री से इंतजार करते हैं. श्रद्धा भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करतीं और अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और स्टाइलिश लुक्स शेयर करती रहती हैं. ईठा की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर हैं. वहीं, फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ईठा में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसव्री से इंतजार कर रहे हैं.

जल्द खत्म होगा इंतजार, सामने आई मिर्जापुर: द मूवी की टीजर रिलीज डेट, पोस्टर ने बढ़ाई सिनेप्रेमियों की हलचल



मिर्जापुर वाला स्टोरी कंटेंट एक बार भौकाल मचाने वाला है, क्योंकि मिर्जापुर द मूवी ने दर्शकों के बीच में जबरदस्त माहौल सेट कर दिया है. अब मिर्जापुर द मूवी की एक झलक देखने के तैयार बैठे दर्शकों के लिए मेकर्स ने बड़ा सरप्राइज छोड़ा है. दरअसल, टीजर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने एक शानदार नया पोस्टर जारी किया है, जिसने फैंस को एक बार फिर मिर्जापुर की दुनिया की एक झलक दिखाई है.

साल की सबसे मोस्ट-अवेडेड फिल्मों में से एक होने के नाते, इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और टीजर की अनाउंसमेंट ने इस बज (चर्चा) को और ज्यादा बढ़ा दिया है. बता दें, आज 25 जून को मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज होने जा रहा है, जिसने अभी से दर्शकों की बेचोनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि पोस्ट की टैगलाइन ने दर्शकों के माइंड को ट्रिगर किया है, जिसमें लिखा है गद्दी है तो हम है. जैसा कि सभी जानते हैं कि मिर्जापुर फ्रेंचाइजी का पूरी स्टोरी कंटेंट राजनीतिक गद्दी पर भी टिका है.

इस पोस्टर के सेंटर में वही आइकॉनिक गद्दी दिखाई दे रही है जिसके दोनों तरफ बंदूकें रखी हुई हैं, जो तुरंत उस पावर स्ट्रगल (सत्ता की जंग), दुश्मनी और ड्रामे की यादों को ताजा कर देती है जिसने मिर्जापुर को एक सनसनी बना दिया था.

भले ही यह पोस्टर फिल्म की कहानी को छुपाकर रखता है, लेकिन यह याद दिलाता है कि मिर्जापुर की दुनिया एक बहुत बड़े पैमाने पर वापसी के लिए तैयार है. कल आने वाले टीजर के साथ, फैंस को एक खास ट्रीट मिलने वाली है क्योंकि उन्हें फिल्म की पहली झलक देखने को मिलेगी.

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेट, मिर्जापुररू द मूवी गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड, पुनीत कृष्णा द्वारा रिटेन और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिशेठ सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस है.

यह फिल्म कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रनी द्वारा को-प्रोड्यूस है. मिर्जापुररू द मूवी में पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) और दिव्येंद्रु शर्मा (मुन्ना भैया) जैसे लोकप्रिय सितारों के साथ-साथ जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हैं. 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक भव्य रिलीज के लिए तैयार है.

वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई गलती



वर्चुअल मीटिंग्स अब आम हो गई हैं। चाहे ऑफिस की हो या अन्य किसी तरह की, इनका सही तरीके से संचालन करना जरूरी है ताकि पेशेवर छवि बनी रहे। सही कपड़े, बैकग्राउंड, समय पर ध्यान देना और तकनीकी तैयारी रखना अहम है। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि आप बोलते समय म्यूट बटन का उपयोग करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। इस लेख में हम आपको वर्चुअल मीटिंग्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते जा रहे हैं।

सही कपड़े पहनें: वर्चुअल मीटिंग्स के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। भले ही आप घर पर हों, पेशेवर दिखना अहम है। औपचारिक कपड़े पहनें ताकि आपकी पेशेवर छवि बनी रहे। अगर आप ऑफिस के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं तो वही कपड़े वर्चुअल मीटिंग्स के लिए भी अच्छे रहते हैं। इससे आप खुद को अधिक पेशेवर महसूस करेंगे और आपकी छवि भी बेहतर बनेगी। उचित कपड़े आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मीटिंग का माहौल भी गंभीर बनाते हैं।

बैकग्राउंड का ध्यान रखें: मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड का ध्यान रखना भी जरूरी है। साफ-सुथरा और व्यवस्थित बैकग्राउंड रखें। अगर संभव हो तो दीवार पर कोई बड़ा चित्र न लगाएं क्योंकि इससे ध्यान भटक सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचें। एक साधारण और पेशेवर बैकग्राउंड सबसे अच्छा विकल्प होता है। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनेगी, बल्कि सामने वाले को भी आपके माहौल का सही अंदाजा मिलेगा।

समय पर उपस्थित रहें: वर्चुअल मीटिंग्स में समय पर आना बहुत जरूरी है। समय पर आने से आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है और आप अपने साथियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी कारणवश आप लेट हो रहे हैं तो पहले से ही संदेश कर दें कि आप थोड़ी देर से आएंगे। इससे सामने वाले को आपकी गंभीरता का पता चलेगा और वे आपकी स्थिति को समझेंगे। हमेशा समय का पालन करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

म्यूट बटन का उपयोग करें जब आप बोलते नहीं हों तो म्यूट बटन का उपयोग करना न भूलें। इससे बैकग्राउंड शोर से बचा जा सकता है और आपकी आवाज साफ-साफ सुनाई देगी। अगर आप किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए बोलने वाले हैं तो पहले म्यूट बटन अनम्यूट करें और फिर बोलें। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है बल्कि आप अपनी बात भी अच्छे से रख पाते हैं। सही तरीके से म्यूट बटन का उपयोग करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

ध्यान केंद्रित रखें: मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और सही तरीके से जवाब दे सकें। अगर आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो आप मीटिंग की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। अपने फोन या अन्य उपकरण को साइलेंट मोड पर रखें ताकि कोई भी विचलित न हो। इस तरह आप वर्चुअल मीटिंग्स को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपनी पेशेवर छवि को बनाए रख सकते हैं।